

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 917]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 — पौष 10, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 27/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच (127).— छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(69), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्टिप्स और इसी प्रकार के पदार्थों से बने व्युत्तित और अव्युत्तित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच (127).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच(127), दिनांक 31-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2019

NOTIFICATION  
No. 27/2019- State Tax (Rate)

No. F-10- 53/2019/CT/V (127). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 1/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(69), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule II - 6%, - serial numbers 80AA and 171A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule III - 9%, after serial number 163A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely: -

"163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 28/2019—राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच (128).— छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(80), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 41 के समक्ष,-

- (क) कॉलम (3) में, अंक "50", उन दोनों जगहों पर जहां-जहां यह आए हों, के स्थान पर अंक "20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(5)

बशर्ते कि पट्टे पर दिए गए प्लाट्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना होगा जिसके लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात् किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु;

बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परिवीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी;

बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्टाकर्ता, मूल पट्टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी राज्य कर की उतनी राशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने की स्थिति में भारित "अपफ्रंट रकम" देय होता, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे।

बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्टाकर्ता का मूल पट्टाग्राही या तदंतर का पट्टाग्राही या उप पट्टाग्राही के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लाट्स का तदंतर पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तों में यह भी उल्लेख होगा कि उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए मूल पट्टाग्राही को मूल पट्टाकर्ता द्वारा प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने पर राज्य कर से छूट प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच (128).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच(128), दिनांक 31-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2019

#### NOTIFICATION

No. 28/2019- State Tax (Rate)

No. F-10- 53/2019/CT/V (128).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 12/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(80), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 41, -

- in column (3), for the figure "50", at both the places where they occur, the figure "20" shall be substituted;
- for the entry in column (5), the following entries shall be substituted, namely, -

(5)

"Provided that the leased plots shall be used for the purpose for which they are allotted, that is, for industrial or financial activity in an industrial or financial business area:

Provided further that the State Government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the State Government in this regard:

Provided also that in case of any violation or subsequent change of land use, due to any reason whatsoever, the original lessor, original lessee as well as any subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of State tax, as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of the plots but for the exemption contained herein, along with the applicable interest and penalty:

Provided also that the lease agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee, or sub- lessee, as well as any subsequent lease or sale agreements, for lease or sale of such plots to subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and conditions, the fact that the State tax was exempted on the long term lease of the plots by the original less or to the original lessee subject to above condition and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

सं. 29/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच (129).— छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(81), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को ऐसे किसी मोटर वाहन को किराए पर देकर दी जाने वाली सेवा जिसे यात्रियों को लाने ले जाने के लिए तैयार किया गया हो और जहां ईंधन का खर्च भी सेवा के प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले प्रतिफल में शामिल हो।	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो कि किसी बॉडी कारपोरेट को सेवा की आपूर्ति करता हो और और सेवा के प्राप्तकर्ता से 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर वसूल करने वाली इनवायस जारी न करता हो।	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित हो।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच (129).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-53/2019/वाक/पांच(129), दिनांक 31-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2019

**NOTIFICATION**  
No. 29/2019- State Tax (Rate)

No. F-10- 53/2019/CT/V (129).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 13/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(81), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient, provided to a body corporate.	Any person, other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging State tax at the rate of 6 percent. to the service recipient	Any body corporate located in the taxable territory."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.